

कृषि ऋण माफी

प्रलिस के ललल:

गैर-नषलपादतल परसलंपततल, कृषल कषेत्तर, कृषल ऋण माफी ।

मेन्स के ललल:

बैंकगल कषेत्तर और एनबीएफसी, वकलस से संबंघतल मुददे, सरकलरी नीतलतलँ और हसुतकषेप, वृदघलँ वकलस, कृषल ऋण माफी और संबंघतल मुददे ।

चरुल में कतुँ?

हलल ही में वरुष 2022 के उतुतर परदेश वघलनसभल चुनलव के ललल एक रलषुदरीय रलजनीतकल दल ने कृषल ऋण माफी की घुषणल की है ।

कृषल ऋण माफी कल अरुथ:

- कृषल ऋण माफी कल अरुथ कसलनों की सलहलतल के ललल रलजतुँ दवलरल घुषतल कृषल ऋण माफी तुलनलओँ से है ।
- जब खरलब मनसून तल परलकृतकल आपदल की सुथतलँ उतुपनून हुती है, तु कसलन ऋण चुकलने में असमरुथ हु सकते हैं । ऐसी सुथतलँ के कलरण उतुपनून संकट अकुसर रलजतुँ तल केंदर कु गुरलमीणुँ कु रहत देने के ललल परेरतल करता है, जसलमें ऋण की मलतुरल में कमी करना तल पूरण छुट परदलन करना शलमलल है ।
- ऐसी सुथतलँ में केंदर तल रलजतु कसलनों की देनदलरी कु गुरहण करते हैं और बैंकुँ कु चुकलते हैं । इस परकलर की छुट परलतु: चतुनलतुमक हुती है अरुथलतु इसमें कुछ वशलषलट परकलर के ऋण, कसलनुँ की शुरेणतुँ तल ऋण सुरुत ही तुगुत हुते हैं ।
- ऋण माफी के तहत मूलतु: ऋण कल एकमुशुत नषलटलन कतुल जलतल है । हललुकलँ पछलले दु दशकुँ में ऐसी तुलनलओँ की घुषणल नतुलमतलतल के सलथ हुई है, तु हलरत में कृषल कषेत्तर के पुरलने संकट कल संकेत है ।
- हललुकलँ इस परकलर की मलंगुँ कुवडल-19 के बीच लुकडलउन के कलरण आतुलवकल के नुकसलन के मदुदेनतुर अधकल वैध लगतल है, फरल भी इस तरह की ऋण माफी बैंकगल परणलली और कुरेडलटल संसुकृतल के ललल हलनकलरक सलबतल हु सकतल है ।

हलरत में कृषल ऋण माफी कल इतललस:

- मधुतलकललीन हलरत में कसलनुँ कु ऋण देने कल पहलल दरुज उदलहरण मुहमद-बनल-तुगलक (1325-51) के शलसन में मललतल है, जसलकल उदुदेशुतु गुरलमीणुँ के समकष मुकुतुद ततुकललीन संकट कु कम करना थल ।
 - हललुकलँ बलद में वदलरुह और अकल के पशुचलतु इन ऋणुँ कु फरललज शलह तुगलक ने मलफ कर दतुल थल ।
- आतुरलदी के बलद हलरत में केवल दु रलषुदरवुतलपी ऋण माफी कलरुतुकुरम हुए हैं: वरुष 1990 और वरुष 2008 में ।
 - सुवतुतर हलरत में पहली रलषुदरवुतलपी कृषल ऋण माफी वरुष 1990 में वल.पी. सलह के नेतुतुतुवल वलली सरकलर दवलरल ललगु की गई थी । इसमें सरकलरी खजलने पर 10,000 कुरुडु रुतुए कल हलर पडुल थल ।
 - वरुष 2008 में संतुतुकुतु परगतशील गठबंघन तलनी सुपीए सरकलर दवलरल ललगु की गई कृषल ऋण माफी और ऋण रहत तुलनल में 71,680 कुरुडु रुतुए कल वुतुतु शलमलल थल ।
- तब से लेकर अब तक वलहलनलन रलजतु सरकलरुँ दवलरल इस तरह की तुलनलओँ की घुषणल की गई है ।

Farm loan waivers: So far, so much

10 states have offered write-offs, some more than once. Nearly all states are implementing these waivers with many riders and in a phased manner to dissipate their financial impact, meaning there is a huge gap between eligible beneficiaries and those who have actually got relief so far.

State	Announced on	Limit* (in ₹/lakh)	Total Amount (in ₹/cr)	Beneficiaries** (in mn)
Karnataka	July 5 2018	2	42,165	4.3
Uttar Pradesh	Apr 14 2017	1	36,359	4.4
Madhya Pradesh	Dec 17 2018	2	35,000	3.4
Maharashtra	June 11 2017	1.5	30,500	3.9
Andhra Pradesh	Aug 2 2014	1.5	24,000	4.9
Rajasthan	Dec 19 2018	Full	18,000	3.3
Telangana	Aug 13 2014	1	17,000	3.6
Punjab	June 11 2017	2	10,000	1
Rajasthan	Feb 12 2018	0.5	8,500	2.8
Chhattisgarh	Dec 17 2018	Full	6,100	1.6
Tamil Nadu	May 23 2016	1.5	5,318	1.2
Chhattisgarh	Dec 26 2015	1	129.7	0.5
Jammu & Kashmir	Jan 23 2017	1	2.4	0.1

// *Individual loan not exceeding **Eligible beneficiaries RESEARCH: ZIA HAQ; SOURCE: RBI, PIB (RELEASE DATED 24-JULY-2018), STATE GOVTS

कृषि ऋण माफी के कारण:

- **छोटी भूमि जोत:** भारत में 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के पास 1-2 हेक्टेयर से कम जोत है और खेती के लिये बुनियादी इनपुट की व्यापक कमी है।
- **मानसून पर निर्भरता:** भारत में फसल की उपज और उत्पादन मानसून पर अत्यधिक निर्भर है।
- **ऋण की आवश्यकता:** इस संदर्भ में फसल उत्पादन और खपत एवं दैनिकी जीवन के खर्चों को पूरा करने के लिये किसान परिवारों हेतु ऋण एक महत्वपूर्ण साधन है।
- **करज का जाल:** किसान करज लेकर कृषि में भारी निवेश करते हैं। अगर बारिश की कमी या बाजार की अपर्याप्त मांग के कारण फसल खराब होती है, तो किसान करज में फँस जाते हैं। इसके चलते किसानों की आत्महत्याओं में इजाफा होता है।
 - इस प्रकार कृषि ऋण माफी इस मानवीय संकट का समाधान होती है।

कृषि ऋण माफी से संबंधित मुद्दे:

- **नैतिक खतरा:** ऋण माफी योजनाएँ ऋण अनुशासन को बाधित करेंगी, क्योंकि कृषि ऋण माफी एक अस्थायी समाधान के रूप में कार्य कर सकती है और भविष्य में एक नैतिक खतरा साबित हो सकती है।
 - ऐसा इसलिए है, क्योंकि जो किसान अपने करज का भुगतान कर सकते हैं, वे करज माफी की उम्मीद में इसका भुगतान नहीं करते हैं।
- **अनावश्यक ऋण की समस्या:** कुछ किसान ज़रूरत न होने पर भी अगली ऋण माफी योजना की उम्मीद में ऋण ले लेते हैं। इसका असर उन किसानों पर पड़ेगा जिन्हें वास्तव में ऋण की ज़रूरत है।
- **ऋण तक औपचारिक पहुँच में गिरावट:** ऋण माफी योजनाओं के लागू होने और इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग उद्योग को होने वाले नुकसान के बाद बैंक कृषि क्षेत्र को और अधिक उधार देने से हचिकेंगे।
 - इससे अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता में वृद्धि होती है।
- **बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव:** अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिये भारतीय परिषद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2008 की कृषि ऋण माफी से वर्ष 2009-2010 और 2012-2013 के बीच वाणिज्यिक बैंकों की **गैर-निष्पादति परसिंपत्तियों** में तीन गुना वृद्धि हुई है।
 - यह आगे **साख जमा अनुपात** और **जोखमि-भारति पूंजी पर्याप्तता अनुपात**, परसिंपत्तियों की वापसी तथा बैंकों की इक्विटी के आर्थिक मूल्य को प्रभावित करता है।
 - यह विशेष रूप से बैंकों की रेटिंग को डाउनग्रेड करता है और सामान्य रूप से क्रेडिट मार्केट के कामकाज को अस्थिर करता है।
- **जमाकर्त्ताओं के हितों के वरिद्ध:** बैंक जमाकर्त्ताओं से धन प्राप्त करते हैं और विभिन्न अनुबंधों एवं समझौतों के तहत उधारकर्त्ताओं को धन उधार देते हैं।
 - इस प्रकार ऋण माफी के कारण बैंक को होने वाली हानि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमाकर्त्ताओं के हितों के वरिद्ध है।
 - इसके अलावा बैंकों को जमाकर्त्ताओं के पैसे के संरक्षक होने के नाते, मुख्य रूप से जमाकर्त्ताओं के हितों के संरक्षण द्वारा निर्देशित किये जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- ऐसा प्रतीत होता है कृषि ऋण माफी किसानों के एक सीमित वर्ग को अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकती है। इससे किसानों को करज के दुष्चक्र से बाहर निकलने की बहुत कम संभावना है।
- वर्ष 2008 में अखिल भारतीय कृषि ऋण माफी के पहले दौर के बाद कृषि संकट में कमी का कोई ठोस सबूत नहीं है। लंबे समय में किसानों की आय में सुधार और स्थिर करके उनकी क्षमता को मजबूत करना ही उन्हें इस संकट से बाहर रखने का एकमात्र तरीका है।
- सचिवाई क्षमता और कोल्ड स्टोरेज शृंखलाओं का निर्माण, फसल बीमा कवरेज में वृद्धि, कृषि बिनयादी ढाँचे का निर्माण, तकनीक-सक्षम उत्पादकता में सुधार और बाज़ार की ताकतों व खुले व्यापार हेतु इस क्षेत्र को खोलने जैसे स्थायी समाधान किसानों को बेहतर विकल्प के रूप में लंबे समय में मदद कर सकते हैं।
- यदा राज्य कृषि क्षेत्र में लंबे समय से लंबित सुधारों को तत्परता से और ईमानदारी से लागू करते हैं कृषि संकट और किसानों की आय को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सकता है।
- वैकल्पिक रूप से ऋण माफी को पूर्णतः माफ करने के बजाय ऋण के केवल एक हिस्से को माफ करना इस दिशा में एक सुधार होगा।
- रचनात्मक जुड़ाव की भी आवश्यकता है जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र के अधिशेष श्रमिकों को अधिक उत्पादक क्षेत्रों में ले जाया जा सकेगा और कृषि को सभी लोगों के लिये अधिक लाभदायक एवं टिकाऊ बनाया जा सकेगा।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/farm-loan-waiver-5>

